

ना पत्र में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार आराजी खसरा नंबर 61/9 रकबा 11 बीघा 05 बिरवा मौजा पातुस पटवार हल्का बिरोल में स्थित होने कथन सही होने से स्वीकार है, साथ ही उक्त भूमि मौके पर कृषि भूमि है तथा बतौर कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन तिया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण की भूमि खसरा नंबर 61/9 कृषि भूमि है तथा वक्त खरीद से ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। जब भूमि का उपयोग ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। जब भूमि का उपयोग ही कृषि कार्य के लिये है, तो इसका भू-रूपान्तरण भी करवाया जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मौके पर न तो आवासीय कॉलोनी बसाई गई है न ही आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ कोई रास्ते बनाये गये हैं। इस भूमि के खातेदारों में आपसी सहमति चुन्दड़ी बंट/बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हिस्से अनुसार मुड्डा गड्डी के पत्थर/मुड्डे गाये गये हैं। केवल ऐसे पत्थरों के आधार पर इस कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जाना नहीं माना जा सकता है। इससे सम्बन्धित मौका स्थिति के फोटोग्राफ तौर सबूत जवाब दावा के साथ पेश हैं। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण की भूमि खसरा नंबर 61/9 कृषि भूमि है तथा वक्त खरीद से ही कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण ने टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा मौके पर किसी प्रकार से कृषि कार्य से भिन्न निर्माण इत्यादि नहीं किया गया है। इससे सम्बन्धित मौका स्थिति के फोटोग्राफ बतौर सबूत जवाब दावा के साथ पेश है। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना कतई गलत होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जावे। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण वाद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 बिनाय वाद कतई असत्य झूठा बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। साथ ही वादी जवाब देहन्दागण के विरुद्ध कोई प्रत्येक वाद प्राप्त नहीं होता है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। वादपत्र के पद संख्या 05 व 06 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत में लाने के हैं। वादपत्र के पद संख्या 07 में वर्णित वादी की इस्तदुआं कतई असत्य झूठी बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। वादी जवाब देहन्दागण के विरुद्ध चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं होने से वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावे। बहस प्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पातुस तहसील जैतारण की खसरा संख्या 61/9 कुल रकबा 11-05 बीघा किस्म बाराणी अब्बल कृषि भूमि जिसके प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार हैं, द्वारा उक्त कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के पिलर आदि लगाकर बिना संपरिवर्तन किये उक्त कृषि भूमि का आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ हेतू किया जा रहा है। जो कि टिनेन्सी की शर्तों को भंग करने व कृषि भूमि की उत्पादकता के विरुद्ध हानिप्रद कार्य है। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

उपरोक्त अधिवक्ता एवं
पदेन सहायक बलवदर,
जैतारण तहसील

प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अब देहन्दा द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ ही काम लिया जा रहा है। मौके पर कृषि से भिन्न अन्य कोई उपक्रम/उद्योग/आवासीय निर्माण किया हुआ नहीं है। अतः भू रूपान्तरण भी करवाया जाना आवश्यक नहीं है। मौके पर न तो आवासीय कॉलोनी बसाई है न ही इस प्रयोजनार्थ कोई रास्ते बनाये गये हैं। इस भूमि के खातेदारों ने आपसी सहमति से चुंदड़ीबंट कर अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़े करने से अपने हिस्से की भूमि की मुड़डा गढी करवाई है। केवल ऐसे पत्थरों के आधार पर आवासीय प्रयोजन नहीं कहा जा सकता है।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी बिरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के अनुसार ग्राम पातुस के खसरा संख्या 61/9 रकबा 11-05 बीघा किस्म बारानी अब्बल कृष्ण पालीवाल, चुन्नीलाल एवं राकेश चौहान खातेदार दर्ज है। सक्षम अधिकारी की प्रतिकृति के बिना उक्त भूमि में आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के पिलर लगाकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण के अनुरोध पर न्यायालय हाजा द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से जांच में पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी बिरोल, भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2021 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर मौके पर आवासीय कॉलोनी के प्रयोजनार्थ रखे जाने वाले रास्ते के पिलर लगाये हुए हैं तथा मौके पर उक्त भूमि में प्लॉट काटे हुए हैं। उक्त भूमि का अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है।

भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम पातुस के अनुसार खसरा संख्या 61/9 रकबा 11-05 बीघा किस्म बारानी अब्बल जो प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कृषि भूमि है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है :-

177. अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली - (1) भू-धारक के आवेदन पर अधिकारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(अ) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे के पर दी गई हो, उससे असंगत हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कूल नहीं है, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।


7. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पातुस के खसरा संख्या 61/9 रकबा 11-05 बीघा किस्म बारानी अब्बल जो कि कृषि भूमि है के खातेदार एवं प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ छोड़े जाने वाले रास्तों के पिलर लगाकर तथा मौके पर आवासीय कॉलोनी प्रयोजनार्थ प्लॉटिंग करके अप्राधिकृत रूप से कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, जो वर्तमान में भी जारी है, जिसके लिए उक्त खातेदारान् द्वारा किसी भी

उपखण्ड अधिवासी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

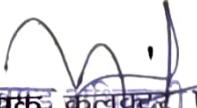
म अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है, तथा न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण खातेदारान् द्वारा जवाब में यह कथन था है कि उनके द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इसके समर्थन में न तो वादग्रस्त आराजी की गिरदावरी प्रस्तुत की है तथा न ही इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। वादग्रस्त भूमि की न्यायालय हाजा द्वारा तलब नवीनतम मौका रिपोर्ट से भी वादपत्र के कथनों एवं दफ्तर के साथ प्रस्तुत पूर्व की मौका रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतः उक्त खातेदारान् का अर्जुक्त प्रत्यय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और सरकार के मध्य की संविदा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदारान् की वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में से अभिधृति अधिकार विलोपित करते हुए भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर के से बेदखल किया जाकर तत्काल कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं वैध है।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी तहसील- पातुस, पटवार हल्का बिरोल तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 61/9, रकबा 1-05 बीघा, किस्म-बारानी अब्बल में से खातेदारान् की सम्पूर्ण भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस भूमि से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर एवं पदेन
अपरखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर एवं पदेन
अपरखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
जिलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

तहसीलदार, जैतारण
लेण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. श्री कृष्ण पालीवाल पुत्र रामरतन
पालीवाल कौम पालीवाल सा0 कुशालपुरा
2. चुन्नीलाल पुत्र भानाराम कौम कुमावत
सा0 कुशालपुरा
3. राकेश चौहान पुत्र दुर्गाराम चौहान कौम
माली सा0 बांजाकुड़ी

जस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,
177 राजस्थान काश्तकारी
धिनियम, 1955

मु0न0 :-87/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू-..... व हाजरी श्री
सीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री सुरेश चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण
नजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादी अंतर्गत धारा-177,
स्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है।
ग्रस्त आराजी सरहद मौजा- पातुस, पटवार हल्का बिरोल तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर
/9, रकबा 11-05 बीघा, किरम-बारानी अव्वल में से खातेदारान की सम्पूर्ण भूमि जो
-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित है, से
वादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज
ते हुए उस पर से प्रतिवादी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त
या जावे। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका
गार्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते
भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.10.2021 इस
र्णय का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर
र्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .
.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें ।

बसिष्ठ मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/05/2022 को जारी
गया।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील		
महनताना वकील		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान		फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक		

मिजान:-

मिजान:-

01-00

नोट- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो,
नहीं दर्ज किया जावे।